जनसत्ता

23 दिसंबर, 2019

उद्योगों को भरोसा

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित उद्योगपतियों और बैंकों को प्रधानमंत्री ने बेखौफ होकर काम करने का जो भरोसा दिलाया है, उससे यह उम्मीद तो बंधती है कि देश को आर्थिक सुस्ती से निकालने के लिए सरकार अब निर्णायक दिशा में तेजी से बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। भारत पिछले एक-सवा साल से आर्थिक मंदी की जैसी मार झेल रहा है, उस सूरत में सरकार और उद्योग जगत दोनों का परेशान होना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार ने मंदी से निपटने के लिए पिछले कुछ महीनों में बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इनका असर दिखा नहीं है। उद्योग संगठन- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जो विश्वास दिलाया है, उस पर सरकार को ठोस अमल करने की जरूरत है। भारत के समक्ष इस वक्त आर्थिक सुस्ती से निपटने की बड़ी चुनौती है, तो देश को पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी है। यह तभी संभव है जब आर्थिक नीतियां उद्योग जगत के अनुकूल होंगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्थिक हालात संतोषजनक नहीं हैं। हालांकि सरकार से लेकर अर्थशास्त्री तक इसके अलग-अलग कारण बता रहे हैं। कोई इसे वैश्विक मंदी का नतीजा बता रहा है, तो कुछ इसे थोड़े समय का प्रभाव बता रहे हैं। पर चिंता की बात यह है कि सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पिछले कुछ महीनों में जो आंकड़े जारी किए हैं, वे अर्थव्यवस्था के हालात बयां करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर विवाद भी सामने आए हैं, कुछेक मौकों पर सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई और खंडन भी किया गया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि देश के आम नागरिक से लेकर उद्योगपतियों तक के मन में एक भय पैदा हुआ है। अर्थव्यवस्था के सामने निवेश बड़ा संकट बना हुआ है। न बाहर से निवेशक आ रहे हैं, न देश के भीतर उद्योगपति निवेश करने और कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। जाहिर है, कहीं न कहीं ऐसी मुश्किलें और भय है जिससे कारोबारी हिचक रहे हैं। भारत की आर्थिक विकास दर कम रहने को लेकर वैश्विक एजेंसियों के जो आकलन आ रहे हैं, उससे भी उद्योगपति सतर्क हैं। ऐसे में कौन निवेश का जोखिम मोल लेगा?

उद्योग जगत को रफ्तार देने में बैंकों की बड़ी भूमिका होती है। उद्योगों को कर्ज मुहैया कराने का बड़ा जरिया बैंक ही हैं। लेकिन भारत का बैंकिंग क्षेत्र जिस संकट का सामना कर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। बैंक एनपीए के बोझ से दबे पड़े हैं, इसलिए खुल कर कर्ज देने से बच रहे हैं। तीन साल पहले नोटबंदी की मार से तबाह हो चुके ज्यादातर छोटे और मझौले उद्योगों के सामने इस वक्त बड़ी मुश्किल यही है कि बैंक उन्हें आसानी से कर्ज नहीं दे रहे। जबकि सरकार और रिजर्व बैंक बैंकों पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि बैंकों की चिंता जायज है कि अगर कर्ज वापसी नहीं हुई तो क्या होगा। सरकार की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। जीएसटी संग्रह में लगातार कमी इस व्यवस्था की खामियों को बताने के लिए काफी है। सरकार के एक पूर्व आर्थिक सलाहकार ने हाल में अर्थव्यवस्था के आइसीयू में जाने की बात कही है। ऐसे में हम कैसे पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन पाएंगे!

मौसम की मार

सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से रेल और हवाई यात्राओं में विलंब, सड़कों पर दुर्घटनाएं और शीतलहर की वजह से बेघर लोगों के मारे जाने की खबरें हर साल का क्रम बन गया है। इस पर काबू पाने के लिए सरकारें और संबंधित महकमे हर साल दम भरते हैं, पर मौसम सामान्य होते ही, सब कुछ पुरानी गति में लौट आता है। फिर अगले साल वही समस्याएं। अभी सर्दी में कोहरा शुरू ही हुआ है कि बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियों के देर से चलने और रद्द होने की खबरें आने लगी हैं। शुक्रवार को खुद रेल विभाग ने कहा कि करीब सौ गाड़ियां देरी से चल रही हैं। यही हाल हवाई जहाजों का है। कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, तो कई विलंब से उड़ान भर सकीं। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर दृश्यता शून्य हो जाने की वजह से गाड़ियों की गति थम गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को किसी जरूरी काम से जाना होगा और उन्हें तय समय पर पहुंचना जरूरी होगा, उनकी क्या स्थिति होती होगी। जिन लोगों ने पहले से टिकट खरीद रखी होगी और ऐन मौके पर उन्हें रेल रद्द होने की सूचना मिलती होगी, तो उन पर क्या गुजरती होगी।

रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। एक बहुत बड़ी आबादी रेल पर निर्भर है। छोटी दूरी की यात्राओं के लिए लोग फिर भी बसों, टैक्सियों आदि का सहारा ले लेते हैं, पर जिन्हें हजारों किलोमीटर दूर जाना हो, उनके लिए रेल के अलावा और कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में अगर उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़े, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। हवाई यात्रा का खर्च उठाने की क्षमता सबमें नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग रेलवे के रहमो-करम पर निर्भर रहते हैं। मगर हवाई जहाजों की स्थिति भी इस मौसम में कोई संतोषजनक नहीं होती। छह-आठ घंटे की देर से उड़ान आम अनुभव है। कई बार मौसम खराब होने के तर्क पर उड़ाने रद्द भी कर दी जाती हैं। समझना मुश्किल है कि जब यह समस्या हर साल की है, तो इस पर काबू पाने के उपायों की तरफ गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता!

ऐसा नहीं कि कोहरे या मौसम खराब होने से दृश्यता शून्य होने की समस्या सिर्फ हमारे देश में होती है। मगर परेशानियां ज्यादातर यहीं उठानी पड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि शून्य दृश्यता वाले वातावरण में हवाई जहाज उतारने का प्रशिक्षण हमारे ज्यादातर पाइलटों को नहीं है। कई साल पहले सरकार ने दावा किया था कि एअर इंडिया के पायलटों को शून्य दृश्यता वाले वातावरण में भी जहाज उतारने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि यह प्रशिक्षण महंगा है, पर सरकार उसका खर्च उठाएगी। मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे कितने विदेशी सैलानियों और विदेश से आने वाली उड़ानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और हर साल कितने पैसों की बर्बादी होती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। यही हाल रेलवे का है। रेलों में अत्याधुनिक उपकरण लगाने का दम करीब पचीस सालों से भरा जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा और गाड़ियों का समय पर और खराब मौसम में भी सुचारु संचालन किया जा सके। मगर आज जब तमाम चीजें कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर निर्भर होती गई हैं, रेलवे पता नहीं क्यों पुरानी प्रणाली के सहारे काम चला रहा है!

कल्पमेधा

वह शासक अत्याचारी है, जो अपनी इच्छा के अलावा कोई नियम नहीं जानता।
- वाल्तेयर

खुशहाली लाने की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

भारत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति चिंताजनक है। देश के अस्सी फीसद से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आम आदमी के धन का एक बड़ा भाग जरूरी सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की मद में खर्च हो रहा है। इस कारण बेहतर जीवन स्तर की अन्य जरूरतों की पूर्ति में वे बहुत पीछे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, 2019 के मुताबिक भारत अपनी मानव विकास रैंकिंग में एक पायदान चढ़ कर एक सौ उनतीसवें पायदान पर पहुंचा गया है। पर हकीकत यह है कि मानव सूचकांक विकास के मामले में भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। नौ दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से मानव संसाधन विकास पर जारी रिपोर्ट में एक सौ नवासी देशों में भारत की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन स्थिति जस की तस ही है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में एक सौ तीसवें पायदान पर था। हालांकि पिछले कुछ सालों में मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति लगातार सुधरी है। इसका बड़ा कारण गरीबी और भ्रष्टाचार में कमी आना है और जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया। भारत में जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की पहल से कमजोर तबके के लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में वर्ष 1990 से 2018 के बीच जीवन प्रत्याशा 11.6 वर्ष बढ़ी है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में साढ़े तीन वर्ष का इजाफा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में ढाई सौ फीसद से अधिक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यूएनडीपी ने भारत को उच्च शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को लेकर चेताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रगति के बावजूद समूह आधारित असमानताएं बरकरार हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रही हैं। इसमें साफ कहा गया है कि भारत में महिलाओं से संबंधित सामाजिक नियमों में भेदभाव किया जाता है, जो महिला सशक्तिकरण में पीछे होने का कारण है।

गौरतलब है कि मानव विकास सूचकांक में देश की प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, जीवन सुरक्षा, सरकार में भरोसा, विदेशी निवेश, न्यायिक प्रणाली पर भरोसा, गरीब लोगों का संरक्षण, रोजगार के अवसरों की स्थिति, ग्रामीण रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। यह सूचकांक इस बात का संकेत है कि कौनसा देश अपने लोगों के पालन-पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण और विकास तथा प्रतिभाओं के उपयोग में कितना आगे है। हालांकि मानव विकास सूची में भारत बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन एक पायदान आगे बढ़ने के भी कई कारण हैं। निश्चित रूप से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत और गरीबों के शौचालय बनवाने, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं लागू करने के साथ-साथ स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ाने से मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है।

सूचकांक बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी तो आई है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले महीने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ष 2019 की सूची जारी की थी। भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के एक सौ अस्सी देशों में भारत अठहत्तरवें स्थान पर आया है। संतोष की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत की सुधरी है और भारत तीन पायदान ऊपर चढ़ा है। पिछले वर्ष इक्यासीवें वें क्रम पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कई बातों का खुलासा हुआ है। पिछले वर्ष छप्पन फीसद नागरिकों ने घूस देने की बात कबूली, जबकि इस साल में ऐसे लोगों की संख्या घट कर इक्यावन फीसद रह गई है।

इस साल की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को देखने के बाद अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में अपेक्षा के अनुरूप मानव विकास सूचकांक नहीं बढ़ रहा है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत सर्वाधिक विकास दर वाला देश है। लेकिन दूसरी ओर भारत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति चिंताजनक है। देश के अस्सी फीसद से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आम आदमी के धन का एक बड़ा भाग जरूरी सार्वजनिक सेवाओ, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की मद में खर्च हो रहा है। इस कारण बेहतर जीवन स्तर की अन्य जरूरतों की पूर्ति में वे बहुत पीछे हैं।

पिछले दशक में भारत में करोड़पतियों-अरबपतियों की तादाद भले बढ़ी हो, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह भी है कि भारत में असमानता का ग्राफ भी तेजी से चढ़ा है। ऑक्सफैम इंडिया की 'आर्थिक असमानता रिपोर्ट 2018' में कहा गया है कि भारत में 1991 के बाद शुरू हुए उदारीकरण के बाद आर्थिक असमानता और अधिक भयावह होती जा रही है। वर्ष 2017 में भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति देश की जीडीपी की पंद्रह फीसद के बराबर हो गई थी। जबकि पांच वर्ष पहले यानी 2012 में यह दस फीसद थी। वर्ष 2017 में भारत में जितनी संपत्ति बढ़ी, उसका तिहत्तर फीसद हिस्सा देश के एक फीसद अमीरों के पास पहुंचा।

निश्चित रूप से मानव विकास की बुनियाद कहे जाने वाले दो महत्त्वपूर्ण पक्षों- रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। देश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। रोजगार में वृद्धि 2015-16 में 2.5 प्रतिशत थी, जो 2016-17 में 4.1 प्रतिशत, 2017-18 में 3.9 प्रतिशत और 2018-19 में 2.8 फीसद रही। हैरानी की बात ये कि देश में रोजगार वृद्धि पिछले दो वर्षों में काफी धीमी पड़ी है। इसी तरह भारतीय युवाओं की प्रतिभा, गुणवत्तापूर्ण जीवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में भारत तिरसठ देशों की सूची में उनसठवें स्थान पर आ गया है। भारत के शैक्षणिक संस्थान वैश्विक शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में बहुत पीछे हैं। इस साल भारत के अधिकांश प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में गिरावट आई है। देश का कोई भी शिक्षण संस्थान अन्य एशियाई संस्थाओं की तुलना में शीर्ष तीस में जगह नहीं बना सका है। आइआइटी-मुंबई पिछले वर्ष के मुकाबले एक स्थान फिसल कर चौंतीसवे स्थान पर आ गया। आइआइटी दिल्ली तियालिसवें स्थान पर और आइआइटी-मद्रास अड़तालीसवें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक शिक्षा अध्ययन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी छात्रों की आबादी भारत में होगी।

इस साल की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि भारत को अपनी जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है। यदि देश को भविष्य की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना है तो युवाओं के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करना होगा। छात्रों को अच्छे रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उन्हें मानव संसाधन और पेशेवर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। देश की नई पीढ़ी को प्रतिभावान बना कर ही रोजगार की संभावनाओं को साकार किया जा सकेगा। इसी में देश के विकास का मूल मंत्र छिपा है।

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सबसिडी व अन्य लाभ सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने और सरकारी योजनाओं में कालाधन नियंत्रण के नए परिदृश्य से देश के आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक लाभ बढ़े हैं। नई स्वास्थ्य नीति के तहत अब स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का ढाई फीसद धन खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, उसे सफलतापूर्वक अमल में लाना होगा। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत जनकल्याण योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू करने को लेकर है। इस मामले में ज्यादातर सरकारें कामयाब नहीं हो पाई हैं। बिना इसके मानव संसाधन का विकास कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है।

संन्यास की अप्रासंगिकता

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

दुनिया मेरे आगे

मानव जीवन को सौ वर्ष का मान कर पच्चीस वर्षों के चार कालखंडों की परिकल्पना में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक हर आश्रम के लिए एक विशिष्ट जीवनशैली का विधान है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन, चरित्र निर्माण और गृहस्थ जीवन में धनार्जन और परिवार पोषण अभीष्ट माना गया है। यह व्यवस्था पचास वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अंतमुर्खी बनाए रखेगी, जिसके बाद वानप्रस्थ कालखंड कार्यकलाप के केंद्र से वह खुद को हटा कर समाज को स्थापित करेगा। पूर्वजों और देवताओं से मिले ऋण को लौटाने का सिलसिला पचहत्तर वर्ष की आयु तक जारी रहेगा, जब शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास व्यक्ति को संन्यास लेने के लिए तत्पर करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित विद्या और कौशल के बिना गृहस्थ जीवन संभव नहीं। समाज के केंद्र में होने से गृहस्थ जीवन एक अनिवार्यता है। उससे जो कुछ मिला उसे वानप्रस्थ में समाज को लौटा देना वांछनीय है। पर उसके बाद संन्यास धारण कर-के शून्य में खो जाने वाली जीवन दृष्टि क्या आज प्रासंगिक है?

जीवन यात्रा के मील के पत्थरों पर आखिरी मंजिल निकट आते देख कर इस राह का मुसाफिर पीछे मुड़-मुड़ कर जीवन की बही के पृष्ठ खोलते हुए अक्सर सोचने लगता है कि क्या खाते में दर्ज करते समय 'डेबिट' और 'क्रेडिट' विवरणों की सही पहचान की गई थी! कम खुशनसीब होते हैं जिन्होंने इस पहचान में घालमेल न की हो। वानप्रस्थ आश्रम की प्रासंगिकता यह थी कि यहां पहुंच कर जीवन की धीमी होती रफ्तार में तब तक लिखे गए खाते को ऑडिट करने का समय मिल पाता था। आश्रमों के कालखंडों की अंकगणित आज बदल चुकी है। इंजीनियरिंग, तकनीक, प्रबंधन और चिकित्सा आदि की पढ़ाई में खास विशेषज्ञता के इस युग में विद्यार्जन खासी पक्की उम्र तक चलता रहता है। उच्चस्तरीय शिक्षा की डगर अब लगभग अंतहीन हो गई है। जब ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम आपस में गड्डमड्ड होते जा रहे हों तो पचास वर्ष की आयु में वानप्रस्थ धारण कर धनार्जन से मुक्ति अधिकतर गृहस्थों के लिए संभव नहीं। जीवन के पांचवें दशक तक पहुंचते-पहुंचते अपनी दक्षता और कौशल के बूते अरबपति बन जाने वाले सौभाग्यशालियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वे अपनी संपदा का उपयोग संसार की वृहत्तर व्याधियों को दूर करने के लिए समर्पित हो रहे हैं। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स ने अट्ठावन साल की आयु में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का पदभार छोड़ कर अपनी अधिकतर संपत्ति मानवमात्र के कल्याण के लिए दान देने का निर्णय लिया, तो दूसरे नंबर के धनवान अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने तिरेपन साल में ही।

अपने देश में सरकार को माई-बाप मान कर केवल उसी से जन-कल्याण के सारे कार्यों की अपेक्षा की परंपरा है। पर हाल के वर्षों में अपनी संपत्ति का बड़ा भाग लोक कल्याण को समर्पित करने वाले धनाढ्यों में विप्रो के अजिम प्रेमजी, इनफोसिस के नारायण और सुधा मूर्ति और अपने बहुमूल्य कला संग्रह को देश के नाम कर देने वाले शिव नाडार जैसों का नाम जुड़ने के बाद अब भारत में भी देश और समाज से मिले ऋण को हजार गुना बढ़ा कर लौटाने वालों की संख्या बढ़ रही है। आइआइटी जैसी संस्थाओं के अपार संपदा अर्जित करने वाले भूतपूर्व विद्यार्थी अब बढ़-चढ़ कर ऐसे कामों में सामने आ रहे हैं। क्या निजी मोक्ष की तलाश में संन्यास धारण करने से कहीं सुंदर विकल्प नहीं है यह कि अपनी सारी क्षमताओं को केंद्रित कर-के इसी धरती को स्वर्ग बनाने की कामना की जाए?

एक तरफ आधुनिक चिकित्साशास्त्र और बढ़ती समृद्धि के चलते औसत आयु लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी के शिक्षाकाल के विस्तार के कारण देर तक चलती रहती हैं। फिर देर से आने वाले वानप्रस्थ को थोड़े अंतराल के बाद ही संन्यास के हवाले कैसे कर दिया जाए? सुदीर्घ वानप्रस्थ को एक लंबे समय तक चलने वाले रिकार्ड की तरह बजाते हुए उन कामनाओं की पूर्ति का समय क्यों न माना जाए जो पारिवारिक चिंताओं के चलते हाशिये पर रख दी गई थीं? बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक मजबूती और राजकीय सहयोग के चलते जीवन के इस कालखंड को चित्रकारिता, संगीत, लेखन, पर्यटन आदि के शौक पूरा करने का समय मान कर जो बहुत धनवान नहीं हैं, वे भी अपने कार्यकलापों से समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। परमार्थ की इस संभावना के आगे संन्यास की कामना निजी मोक्ष का अतिआत्मकेंद्रित दर्शन लगती है। 'यावत्जीवेत सुखं जीवेत' की कामना अब केवल 'ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत' से नहीं पूरी होती। निजी इच्छाओं की पूर्ति में भी समाज का ऋण कई तरह से चुका पाने की संभावनाएं होती हैं। समकालीन परिवेश में दूसरों के लिए जीने के साथ-साथ खुल कर अपने लिए जीने के दर्शन के आगे संन्यास की धारणा अब अप्रासंगिक लगती है!

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अहिंसा का रास्ता

किसी भी कानून का विरोध करने से पहले हमें उसके बारे में तार्किकता की कसौटी पर उसके सकारात्मक और नकारात्मक नतीजों का विश्लेषण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसके बाद नकारात्मक पक्ष को लेकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा विरोध करना, जिसमें सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो, यह कोई स्वतंत्रता नहीं है। हरेक की स्वतंत्रता की सीमा वहीं तक सुनिश्चित होनी चाहिए, जहां तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। इसलिए गांधी जी के अहिंसात्मक मूल्यों अपनाते हुए हम विरोध दर्ज करा सकते हैं। बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था- संविधान कभी गलत नहीं हो सकता है, बल्कि धरातल पर उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए संविधान की रक्षा भी हमारा मूल कर्तव्य है।

● *शैलेश मिश्र, बीएचयू, वाराणसी*

हठधर्मिता का हासिल

लोकतांत्रिक राष्ट्र में अपनी मांगें मनवाने का जरिया हिंसक प्रदर्शन कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हिंसा के द्वारा राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति को आघात पहुंचाया जाना सचमुच निंदनीय है। सरकार को प्रभावित करने के लिए धरना-प्रदर्शन और हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया जा सकता है। लेकिन यह भी दुर्भाग्य लगता है कि जनता को हिंसक प्रदर्शन के लिए बाध्य किया जा है। सवाल है कि आखिर क्यों सरकार अपनी नीतियों को सहसा कानूनी जामा पहना कर जनता पर थोपती है? इसके साथ तत्काल इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती है और साथ ही साथ धारा 144 भी लागू कर दी जाती है, ताकि अवाम की आवाज को दफन किया जा सके। हालिया उदाहरण जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय किए जाने और बाबरी मस्जिद पर कोर्ट निर्णय के साथ देखे जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता में भय व्याप्त करने और असंतोष का भावना घर होने के पीछे सरकार का रवैया जिम्मेदार है। जनता और सरकार का समय रहते संभलना निहायत जरूरी है, जनता को धैर्य रखना होगा। साथ ही सत्ता को अपनी हठधर्मिता का त्याग करना होगा। सरकार को नहीं भूलना होगा कि विध्वंस की बुनियाद पर टिका कोई भी विचार मानवता के लिए खतरा है।

● *अली खान, जैसलमेर*

लोकतंत्र के बरक्स

इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाले हमारे प्रशासन के लोगों की जब तक अतिजरूरी न हो, नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रही है। यह उनके काम करने का तरीका है जो आज की परिस्थितियों का निर्माण करने का कारण है। इसके तमाम उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं। हैदराबाद पुलिस लारा एनकाउंटर पर तत्काल खुशी जाहिर करने वाले लोग आने वाले खतरों को भूल जाते हैं। हमारे यहां पुलिस राज्य का विषय है और अफसोसनाक यह है कि किसी भी राज्य की पुलिस की छवि इतनी उजली नहीं है कि इस तरह के एनकाउंटर के कारण के उनके दावों पर विश्वास किया जा सके। आज इतने सख्त कानून के बावजूद पुलिस अपराधियों में कानून का डर पैदा नहीं कर सकी है। उसके उलट निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा कर उन्हें डराने में वह जरूर कामयाब है। वरना क्या कारण है कि बलात्कार और छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी ओर अपराधी बेखौफ अपराध करते जाते हैं। हैदराबाद पुलिस लारा एनकाउंटर पर तारीफ करने वालों के जेहन में यह प्रश्न क्यों नहीं उठता है कि जब पीड़िता के पिता शिकायत के लिए एक थाने से दूसरे थाने दौड़ रहे थे तो वही पुलिस उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी? ऐसी घटनाएं हमारे देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रही हैं।

● *सुनिल के जैन, कस्तूरबा नगर, रतलाम*

जड़ सोच

हमारे भारतीय समाज का ढांचा रूढ़िवादी, भाग्यवादी और परंपराओं पर आधारित है। इन विशेषताओं के कारण समाज में बहुत-सी कुरीतियां हैं। सामाजिक परंपराओं के आधार पर विभिन्न अवसरों, जैसे शादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर जाति-बिरादरी को अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यय करके सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। सवाल है कि क्या कर्ज लेकर या फिर किसी रास्ते अर्जित धन से शानो-शौकत का प्रदर्शन या फिर विवाह या श्राद्ध के आयोजन से प्रतिष्ठा बढ़ती है? ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं, जब इन अवसरों पर व्यय करने के लिए ऋण लेना होता है। ऐसी परंपराओं और रीति-रिवाजों के कारण लोगों का समाज में सुखी जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। परंपरागत बातों को केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हरेक क्षेत्र में अपनाने का प्रयास किया जाता है, जिनके कारण सहज जीवन जीने में कठिनाइयां आती हैं।

● *सत्यम यादव, प्रयागराज*

इंटरनेट पर पाबंदी

भारत दुनिया का पहला देश है, जहां वर्ष 2012 के बाद से अब तक इंटरनेट तीन सौ बहत्तर बार बंद हो चुका है। असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सरकार इंटरनेट सेवाओं को सबसे पहले बंद करती है। नागरिकता कानून को लेकर असम से शुरू हुआ विरोध अब देशव्यापी हिंसा में तब्दील हो चुका है। यह बेहद चिंता का विषय है। असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए समाज में क्रूरता फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ इंटरनेट को इतनी बार बंद करना शांति के लिहाज से तो सही है, परंतु आंनलाइन व्यापार के लिहाज से कतई उचित नहीं है। आज ज्यादातर लोगों का काम और जीवन इंटरनेट पर आधारित हो चुका है, ऐसे में इससे होने वाली मुश्किलों का अंदाज लगा पाना आसान नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे,लेकिन आमजन की समस्याओं का भी खयाल रखे।

● *गौतम, एमसीयू, खंडवा*

www.readwhere.com